द हिल कल्टिवेटर

वर्ष-1, अंक-8: अप्रैल 2025

जायका कृषि परियोजना-2 की मासिक ई-पत्रिका

THE HILL CULTIVATOR

MONTHLY E-PAPER OF HPCDP (PHASE-II), JICA-ODA

कृषि व बागवानी क्षेत्रों पर खर्च होंगे 2 हजार करोड़ रुपए: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू

मुख्यमंत्री ने हल्दी खरीद पंजीकरण प्रपत्र जारी किया

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि कृषि और बागवानी के क्षेत्र के लिए इस वित्तीय वर्ष में दो हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने दोनों विभागों की समीक्षा बैठक में 24 अप्रैल 2025 को दी। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने एक अन्य बैठक में 7 अप्रैल को हल्दी खरीद पंजीकरण प्रपत्र जारी किया था।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि व बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि व बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका विपणन करने के लिए बेहतरीन व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसी दृष्टिकोण के साथ दुग्ध क्षेत्र के विकास के लिए भी नवोन्मेषी प्रयास किये जा रहे हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश सरकार द्वारा हिम गंगा योजना को प्रथम चरण में पायलट आधार पर हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में आरम्भ किया गया है। मिल्कफैड द्वारा मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में 120 स्वचालित और 32 डिजिटल दूध संग्रहण इकाइयां स्थापित की गई हैं।

इस बैठक में कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक आशीष बुटेल, मिल्कफैड के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर, सचिव पशुपालन रितेश चौहान, मिल्कफैड के प्रबन्ध निदेशक विकास सूद तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हल्दी खरीद के लिए पंजीकरण प्रपत्र जारी किया।

इस बीच मुख्यमंत्री ने हल्दी खरीद के लिए प्रपत्र जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित हल्दी, गेहूं तथा मक्का के समर्थन मूल्य को इस वित्त वर्ष में क्रमश: 90 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है तथा प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा।

यह पहल न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी प्रदान करते हुए किसानों की आर्थिकी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। कृषि विभाग द्वारा इस सम्बंध में किसानों का पंजीकरण किया जाएगा तथा उन्हें प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पंजीकृत किसानों से खरीदी गई कच्ची

हल्दी का स्पाइस पार्क, हमीरपुर में प्रसंस्करण किया जाएगा। प्रोसेस्ट हल्दी का विपणन 'हिमाचल हल्दी' के ब्रांड के नाम से किया जाएगा, जोकि इसे बाजार में अलग पहचान प्रदान करेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार होगा कि राज्य सरकार किसानों से सीधे तौर पर कच्ची हल्दी की खरीद करेगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को आजीविका के अवसर भी प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक पद्धति से उगाए गए गेहूं को 60 रुपये प्रतिकिलो और मक्की को 40 रुपये प्रतिकिलो के समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षों में दूध के समर्थन मूल्य में भी 21 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। वर्तमान में गाय के दूध को 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध को 61 रुपये प्रति लीटर के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है।

बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह खाची तथा सचिव कृषि सी. पालरासू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कृषि क्षेत्र विकास के लिए रिमोट सेंसिंग की अहम भूमिका: प्रो. चन्द्र कुमार

देहरादून/ शिमला 25 अप्रैल। कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने 25 अप्रैल को भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून में कृषि अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से मौसम के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का दक्षतापूर्वक समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है।

कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक नवोन्मेषी पहल की हैं। प्रदेश में हिम कृषि योजना आरम्भ की गई है, जिसके तहत विभिन्न कलस्टरों में गतिविधियां आरम्भ की गई हैं। किसानों के उत्थान के लिए हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण संवर्धन परियोजना के तहत 154 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे कृषि यंत्रीकरण और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रतिकिलो समर्थन मूल्य घोषित किया है।प्रो. चन्द्र कुमार ने भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का किसानों और बागवानों को लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि रिमोट सेंसिंग तकनीक को कृषि क्षेत्र के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषि अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण के लिए इस संस्थान में भेजा जाएगा। इस संस्थान में प्रदेश के 25 कृषि अधिकारियों के लिए 21 से 26 अप्रैल तक छ: दिवसीय रिमोट सेंसिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

इस अवसर पर संस्थान के निदेशक आरपी सिंह तथा कृषि निदेशक कुमुद सिंह भी उपस्थित थीं।

जायका कृषि परियोजना में बजट आश्वासनों का सख्ती से होगा क्रियान्वयन: डॉ. सुनील चौहान

हमीरपुर, 21 अप्रैल। परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने जायका कृषि परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा घोषित 2025-26 के बजट आश्वासनों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. चौहान कृषि विज्ञान केंद्र, बड़ा (नौदान) में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन

कर रहे थे। इस कार्यक्रम में परियोजना के जिला एवं ब्लॉक प्रबंधकों तथा उनके तकनीकी स्टाफ के लिए सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम), सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) एवं फसल विविधीकरण योजना (सीडीपी) पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपने उद्घाटन भाषण में परियोजना निदेशक ने हिमाचल प्रदेश बजट 2025 -26 में दिए गए आश्वासनों पर विस्तार से प्रकाश डाला। बजट आश्वासन में परियोजना क्षेत्रों में 154 करोड़ रुपये खर्च करने; 100 सिंचाई उप परियोजनाएं किसान संघों को सौंपना; मशीनीकरण के लिए परियोजना क्षेत्रों में 10 करोड़ रुपये खर्च करना शामिल हैं। इनके अतिरिक्त कृषक सहायता घटक के तहत 1500 प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुख्य रूप से सब्जी की खेती के लिए 4000 प्रदर्शन प्लाट तथा मोटे आनाज और अन्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 2400 प्रदर्शन प्लाट लाभान्वित किसानों के खेतों में लगवाए जायेंगे। बजट 2025-26 के आश्वासन के अनुसार राज्य में हल्दी की व्यावसायिक खेती और प्रसंस्करण भी शामिल है।

डॉ. सुनील चौहान ने सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए सभी कार्यक्रमों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से क्रियान्वित करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक उप-परियोजना क्षेत्र में निगरानी प्रणाली विकसित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कृषक परिवारों की समृद्धि बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक अन्वेषण हेतु प्रमुख फसलों की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य अतिथि डॉ. सुनील चौहान ने किचन गार्डनिंग मैनुअल के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री बीएस संधू, वरिष्ठ सलाहकार, श्री प्रदीप शर्मा वित्त अधिकारी तथा केवीके के प्रतिनिधि डॉ. नवनीत जरयाल विषय वाद विशेषज्ञ, उप परियोजना निदेशक डॉ. राजेश कमार, डॉ. करतार सिंह तथा पीएमसी के कृषि विशेषज्ञ डॉ. आरके शर्मा, डॉ. पीएन शर्मा तथा डॉ. आरएस ठाकुर उपस्थित थे, जबकि डॉ. डीडी शर्मा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वयन किया।

जायका मिशन ने प्रोजेक्ट की गति बनाए रखने की उम्मीद जताई

जायका रिव्यू मिशन ने ऐलान किया कि दिसम्बर में अंतरराष्ट्रीय जायका कृषि कार्याशाला होगी, मिशन ने परियोजना की वेबसाइट www.hpjicaagriculture.com का किया विमोचन

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश जायका कृषि परियोजना के दौरे के चौथे दिन गुरुवार 1 मई को दो सदस्यीय जायका समीक्षा मिशन द्वारा राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू), हमीरपुर में समापन बैठक में भाग लिया जिसमें डॉ. आशीष शर्मा, एसएमएस, एसपीएमयू ने कार्यवाही का संचालन किया और पिछले तीन दिनों में चार उप-परियोजनाओं- कसारला और कटली नाला (जिला मंडी), जोबरंग और यारती-तिन्नो (लाहौल और स्पीति जिला) में जायका समीक्षा मिशन के दौरे का संक्षिप्त विवरण दिया।

इस समीक्षा मिशन में परियोजना निर्माण सलाहकार सुश्री इनागाकी युकारी विकास विशेषज्ञ सुश्री निष्ठा वेंगुर्लेकर शामिल हैं।

परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान के निर्देश पर, पीएमसी के सह-टीम लीडर अनिल अग्रवाल ने विभिन्न परियोजना घटकों पर जायका कृषि परियोजना को समर्थन पर एक प्रस्तुति दी। बैठक में वरिष्ठ सलाहकार बीएस संधू, वित्त अधिकारी प्रदीप कुमार, उप परियोजना निदेशक डॉ. राजेश कुमार, डॉ. डीडी शर्मा, डॉ. करतार सिंह और परियोजना के एसपीएमयू के विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। डॉ. बाला एसोसिएट निदेशक, सह-टीम लीडर, पीएमसी के विषय विशेषज्ञ और एएफसी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। डॉ. सुनील चौहान ने विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण दिया और कृषि उपज और उत्पादों के लिए विपणन नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।

परियोजना द्वारा प्रकाशित किचन गार्डनिंग मैनुअल (अंग्रेजी और हिंदी) भी समीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत किए गए। मिशन के सदस्यों ने तकनीकी सहयोग परियोजना के ज्ञान बैंक का उपयोग करके किसान परिवारों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मजबूत करने की ओर इशारा किया।

मिशन के सदस्यों ने निकास नीति समय-सीमा को तैयार करने और उल्लेख करने पर जोर दिया, और हितधारकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

मिशन के सदस्यों के द्वारा समापन बैठक के दौरान www.hpjicaagriculture.com के डोमेन नाम के साथ परियोजना की वेबसाइट भी लॉन्च की।

परियोजना खण्ड स्तर पर किसान समर्थन पर समीक्षा बैठकें हुई

जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर

पालमपुर 28 अप्रैल। आगामी खरीफ सीजन 2025-26 के लिए निर्धारित वार्षिक कार्य योजना (एपीओ) के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 26 और 28 अप्रैल को जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) पालमपुर के अंतर्गत ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाइयों (बीपीएमयू) की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य परियोजना की प्रगति की समीक्षा करना तथा विशेष रूप से किसान सहायता घटक के तहत रणनीति तैयार करना था। बैठकों की अध्यक्षता जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. योगेंद्र पॉल कौशल ने की जिसमें उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रथम चरण की सभी उप-परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए और उनकी परियोजना पूर्णता रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाये और किसान पहुंच सड़कों, खेतों की बाड़बंदी जैसी इंजीनियरिंग गतिविधियों के लिए सटीक और व्यावहारिक अनुमान तैयार कर समय पर प्रस्तुत करें। बैठक में किसान सहायता घटक पर विशेष चर्चा हुई, जिसके अंतर्गत किसानों के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शन, समूह गठन एवं सब्जी उत्पादन जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई। विषय वाद विशेषज्ञ रजनीश शर्मा ने बताया कि बड़ा, हमीरपुर में 21 और 22 अप्रैल को आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के अनुसार सभी बीपीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन गतिविधियों की विस्तृत योजना बनानी है और उसे प्रभावी रूप से लागू करना होगा। इसके अतिरिक्त, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए पोषक रसोई उद्यान, जायका-सब्जी उद्यान एवं उत्पादक रुचिहित समूहों (सीआईजी) पर सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। इन प्रयासों का अंतिम उद्देश्य किसानों के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन करना है जिससे उन्हें बेहतर बाजार, प्रशिक्षण और आय के अवसर प्राप्त हो सकें।

बैठक में सभी ब्लॉक परियोजना प्रबंधकों, तकनीकी सहायकों और संबद्ध अधिकारियों ने भाग लिया और परियोजना के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

चुवाड़ी में किसान मेले का आयोजन

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया रहे मुख्य अतिथि

चुवाड़ी, जिला चम्बा, 3 अप्रैल। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा चुवाड़ी में एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय कुलदीप सिंह पठानिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मेले का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों से अवगत कराना तथा उन्हें प्रगतिशील कृषि की ओर प्रेरित करना था। मेले में कृषि विभाग के द्वारा कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिनमें हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 द्वारा चम्बा जिले में संचालित गतिविधियों की विशेष प्रस्तुति शामिल रही। जायका परियोजना की ओर से खंड प्रबंधन इकाई चम्बा के अंतर्गत भटियात सर्कल की उप-परियोजनाओं से जुड़े लाभार्थी किसानों ने भी भाग लिया। खंड परियोजना प्रबंधक, चम्बा डॉ. भानु प्रताप ने मुख्य अतिथि पठानिया को जायका के तहत जिला चम्बा में संचालित

विभिन्न विकासात्मक कार्यों- जैसे कूहल निर्माण, सब्जी उत्पादन प्रोत्साहन, जैविक खेती, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अवगत करवाया। मुख्य अतिथि ने सभी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। अपने संबोधन में पठानिया ने कहा कि एचपीसीडीपी-जायका जैसी परियोजनाएं प्रदेश के किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई की सुविधा, तकनीकी प्रशिक्षण और फसल विविधीकरण का लाभ मिल रहा है, जिससे फसल और सब्जियों की उत्पादकता में बंपर बढ़ोतरी संभव हो रही है।

ऐसी परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने और युवाओं को कृषि में जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वह सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं और वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती कर अधिक आय अर्जित करें।

मेले में किसानों, स्थानीय प्रतिनिधियों, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा कृषि से जुड़े विभिन्न संगठनों की भागीदारी रही। यह आयोजन किसानों के लिए जानकारी का खजाना साबित हुआ और उन्हें कृषि में नवाचार अपनाने की नई दिशा प्रदान की।

किसानों को सब्ज़ी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही कृषि जायका परियोजना

देहरा, 29 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग एवं हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 द्वारा किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक अभिनव पहल के अंतर्गत विभिन्न उप-परियोजनाओं में मौसमी सब्जियों के पौधों का नि:शुल्क वितरण किया गया। इस अभियान के तहत किसानों को टमाटर, मिर्च, लौकी, खीरा, करेला सहित अन्य पौधों की पौध वितरित की गई। यह पहल न केवल किसानों को सब्जी उत्पादन की ओर प्रेरित कर रही है, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध करवाकर उनकी कृषि आय को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस अवसर पर किसानों को पौधों की उचित देखभाल, जैविक खेती की विधियों और उन्नत कृषि तकनीकों की भी जानकारी दी, जिससे वे अधिक उत्पादन के साथ-साथ मिट्टी की सेहत और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकें। कई किसानों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में एक सुनहरा अवसर बताया। उनके अनुसार, इस तरह की योजनाएं न केवल कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देती हैं, बल्कि जैविक खेती जैसी स्थायी पद्धतियों को भी मुख्यधारा में लाने में सहायक सिद्ध होती हैं। जायका परियोजना की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच सकारात्मक परिवर्तन लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है।

56.72 लाख से बनी चमडुहल कूहल सिंचाई योजना किसानों को सौंपी

104 लाभान्वित किसानों को होगा लाभ

पालमपुर, 26 अप्रैल 2025। हिमाचल प्रदेश में किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल को धरातल पर उतारते हुए हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के तहत चमडुहल कूहल बहाव सिंचाई योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह परियोजना नगर निगम पालमपुर के वार्ड नंबर 7 चिम्बलहार, विकास खंड भवारना में क्रियान्वित की गई है।

इस उप-परियोजना के निर्माण में कुल 56.72 लाख की लागत आई। परियोजना के अंतर्गत निर्मित सिंचाई प्रणाली से 104 लाभार्थी किसान परिवारों की कुल 39.92 हैक्टेयर भूमि को नियमित सिंचाई सुविधा मिल सकेगी, जिससे किसानों की कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। यह कूहल अब कृषक विकास संघ (केवीए) चमडुहल कूहल को सौंप दी गई है, जो इसके संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी निभाएगा। सिंचाई सुविधा मिलने से क्षेत्र के किसान काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इससे अब वे खरीफ सीजन में समय पर बुवाई कर सकेंगे। योजना के उद्घाटन अवसर पर खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर द्वारा चिम्बलहार में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला परियोजना प्रबंधक योगेंद्र पाल कौशल, विषयवाद विशेषज्ञ रजनीश शर्मा, खंड परियोजना प्रबंधक अमित भूषण, कृषि विशेषज्ञ, निर्माण अभियंता एवं अन्य परियोजना अधिकारी और नगर निगम पालमपुर के वार्ड पार्षद संजय डोगरा, कृषक विकास संघ चमडुहल के प्रधान, उप-प्रधान और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

इस मौके पर जिला परियोजना प्रबंधक योगेंद्र पाल कौशल के कहा कि यह योजना क्षेत्रीय किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देने के साथ-साथ न पानी के प्रभावी प्रबंधन और फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा देगी। यह हिमाचल प्रदेश सरकार और जायका की साझेदारी का एक और प्रमाण है कि कृषि क्षेत्र को समृद्ध और टिकाऊ बनाने के लिए जमीनी स्तर पर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

सिंचाई योजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किए गए निरीक्षण

धर्मशाला। फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रहे हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के अंतर्गत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया।

इसके पश्चात एफआईएस कटुहल कूहल का दौरा किया गया, जहां हेड वियर पर किए गए कंक्रीट कार्य की गुणवत्ता जांच के लिए रीबाउंड हैमर टेस्ट किया गया। यह परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप टिकाऊ और मजबूत है। अंत में, निरीक्षण दल ने एफआईएस मंडल कूहल का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में जो खामियां पाई गईं। इस पर ठेकेदार के प्रतिनिधि को सभी दोषपूर्ण कार्यों को शीघ्र सुधारने और निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों एवं तकनीकी विनिर्देशों का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश भी दिये गए। यह निरीक्षण परियोजना की पारदर्शिता, गुणवत्ता नियंत्रण और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

निरीक्षण की शुरुआत एफआईएस दडुहल कूहल से की गई, जहां निर्माण कार्यों की प्रगति एवं आगामी कार्यों के निष्पादन को लेकर केवीए से विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने कार्य की समयबद्धता के साथ-साथ गुणवत्ता मानकों के पालन पर विशेष जोर दिया।

कलूर पंचायत में कृषि जागरूकता शिविर आयोजित

नादौन। नादौन विकास खण्ड की पंचायत कलूर के गांव गारनी फरनाट में कृषि विभाग द्वारा फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कृषकों को कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन बारे विस्तार से बताया गया। शिविर की अध्यक्षता कलूर पंचायत के प्रधान राजेन्द्र कुमार ने की। शिविर में खण्ड परियोजना प्रबंधक डॉ. जीत राम व कृषि अधिकारी पूजा भारद्वाज ने किसानों को परियोजना के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य कृषि आधारित रोजगार सृजन करने तथा उच्च गुणवता, कीमत वाली फसलों के मूल्यवर्धन और विपणन के लिए स्थाई विविधीकरण के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है। शिविर में वार्ड पंच मोनिका सहित करीब 40 किसानों ने भाग लिया।

इस अवसर पर गारनी कृषक विकास एसोसिएशन का गठन भी किया गया, जिसमें मदन लाल को सर्व सम्मति से प्रधान चुना गया। जबकि उप प्रधान चमन लाल, सचिव मीना कुमारी, कोषाध्यक्ष अमित कुमार व बरसला देवी, राजेन्द्र कुमार व रमेश चंद को सदस्य चुना गया।

मण्डी में सिंचाई योजना काटली नाला किसानों को सौंपी

मण्डी 11 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करने के लिए खण्ड परियोजना प्रबंधक इकाई, मण्डी द्वारा बहाव सिंचाई योजना काटली नाला से ननावां पपलेहरा का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर यह परियोजना दिनांक 11.04.2025 को सम्बंधित कृषक विकास संघ को डॉ. राजेश जसवाल खण्ड परियोजना प्रबंधक, मण्डी द्वारा डॉ. खूब राम, विषयवाद विशेषज्ञ कार्यालय जिला परियोजना प्रबंधक इकाई मण्डी की उपस्थिति में हस्तांतरित की गई। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 1428 मीटर लम्बा खेत पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया उससे किसानों द्वारा खेतों में उगाई गई सब्जियां व अन्य फसलें बाजार व सब्जी मण्डी में आसानी से पहुंच सके और इसके साथ यहां पर 830 मीटर लम्बी सोलर फेंसिंग और 1839 मीटर मुख्य कूहल के साथ-साथ सिंचाई के लिए 2132 मीटर एच डीपीई जल वितरण पाइपों का भी उपयोग किया गया। इस परियोजना में 23.90 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई, इससे 34 किसान परिवार लाभान्वित होंगे।

इस उप परियोजना के निर्माण हेतु 1.34 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

हस्तान्तरण के दौरान कृषक विकास समूह के प्रधान दुर्गा सिंह, सचिव नन्द लाल ठाकुर व प्रबंन्धक समिति के सदस्य तथा अन्य लाभार्थी उपस्थित थे।

खण्ड परियोजना प्रबंधक, मण्डी डॉ. राजेश जसवाल ने कृषक समूह को नकदी फसलों के उत्पादन एवं विपणन के बारे में जानकारी दी व विषयवाद विशेषज्ञ डॉ. खूब राम ने कूहल के रख-रखाव के बारे में बताया। इस समारोह में डॉ. हंस राज कृषि विकास अधिकारी व खण्ड परियोजना प्रबंधक इकाई मण्डी के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जायका परियोजना सोलन की टीम ने जदारी, ध्याडी, धाली का किया दौरा

सोलन 11 अप्रैल। जायका टीम सोलन ने बीपीएम डा. अरुण शर्मा एवं एसएमएस डा. रविंद्र शर्मा की अगुवाई में जदारी, ध्याडी, धाली साइट का दौरा किया। इस दौरान प्रोजैक्ट के अंतर्गत आने वाले किसानों के एक समूह के साथ चर्चा की, जिसमें खरीफ सीजन में नए इंटरवेंशन के माध्यम से डेमोस्ट्रेशन करने के तरीकों पर विचार किया गया जो कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है।

बीपीएम ने फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी डेमोस्ट्रेशन पर भी चर्चा की, जिसमें मक्की फसल और सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग के बारे में विचार किया - गया। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ भी चर्चा की गई जिसमें उनके कार्य और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई और महिलाओं के ग्रुप से उनकी सहायता प्रोजेक्ट के माध्यम से कैसे की जा सकती है पर गहन चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि चर्चा के माध्यम से किसानों और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने का अवसर मिला, जिससे इस प्रोजेक्ट को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। इस मौके पर केवीए प्रधान प्रद्युमन ठाकुर सभी मेम्बर और महिला मंडल जदारी की प्रधान सुषमा ठाकुर व ग्रुप की महिलाएं, बीपीएम यूनिट से डा. तनवी सूद, दीपांशी उपस्थित रहे।

जायका परियोजना की बग्गी सिंचाई योजना को किसानों को सौंपा

72 लाख रुपए की सिंचाई योजना से 64 किसान परिवार होंगे लाभान्वित

सरकाघाट 5 अप्रैल। उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत पौंटा के अंतर्गत गांव बग्गी में निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना को खंड परियोजना प्रबंधन इकाई सरकाघाट द्वारा कृषक विकास संघ को औपचारिक रूप से समर्पित किया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता एसडीएम भोरंज शशिपाल शर्मा ने की। कार्यक्रम में विशेष रूप से जिला परियोजना अधिकारी हेमराज वर्मा, खंड परियोजना अधिकारी अश्वनी कुमार और जायका परियोजना से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जायका प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और उन्हें अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि एसडीएम शशिपाल शर्मा ने कहा कि इस सिंचाई योजना के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे खेतीबाड़ी को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक सुधार आएगा। जिला परियोजना अधिकारी हेमराज वर्मा ने बताया कि मात्र 9 महीनों के भीतर इस परियोजना को पूर्ण किया गया है, जिसकी कुल लागत 72 लाख रुपए है। इस योजना से लगभग 19.97 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी और 64 किसान परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। ग्रामीणों ने इस योजना के लिए प्रशासन और परियोजना अधिकारियों का आभार जताया तथा कहा कि इससे उन्हें अपनी कृषि योग्य भूमि को अधिक उत्पादक बनाने में सहायता मिलेगी।

हि.प्र. जायका कृषि परियोजना की ओर से आभार

हिमाचल प्रदेश जायका कृषि परियोजना की ओर से मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार और बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी एवं कृषि-बागवानी सचिव डॉ. सी. पॉलरासु के अतिरिक्त जायका समीक्षा मिशन में शामिल परियोजना निर्माण सलाहकार सुश्री इनागाकी युकारी और विकास विशेषज्ञ सुश्री निष्ठ वेंगुर्लेकर का आभार व्यक्त हूं, जिन्होंने इस परियोजना में काम कर रहे स्टाफ को किसानों की खुशहाली के लिए प्रेरणा दी है, ताकि ग्रामीण आर्थिकी मजबूत हो सके।

हि.प्र. जायका कृषि परियोजना की ई-पत्रिका, 'द हिल कल्टीवेटर' में सरकार के लोकप्रिय कृषि नेता मुख्यमंत्री और कृषि एवं बागवानी मंत्रियों और सरकार के दोनों विभागों के सचिव और जायका समीक्षा मिशन से जुड़े समाचार प्रकाशित किए गए हैं। इस जानकारी को हम परियोजना क्षेत्र के किसानों और हितधारकों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि सरकार और जायका की नीतियों व सोच का प्रसार कर सकें।

यहां मैं परियोजना के जिला व ब्लॉक परियोजना प्रबंधकों और उनके स्टाफ के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, बड़ा (नादौन) में हुए दो दिवसीय प्रशिक्षण का भी जिक्र कर रहा हूं। इस शिविर में परियोजना स्टाफ ने परियोजना से संबंधित बजट आश्वासनों को पूरा करने का संकल्प भी दोहराया। मैं परियोजना स्टाफ और हितकारकों को जायकों समीक्षा मिशन के दौरे और प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने के लिए दिए गए उनके योगदान के लिए धन्यवाद करता हूं।

परियोजना में चल रहे कार्यों के उल्लेख भी इस ई-पत्रिका में मिलेगा।

मुझे आशा है कि हम सब मिलकर नए वित्तिय वर्ष 2025-26 में सभी नए जोश के साथ परियोजना के कार्यों को हम तेजी से पूरा करके, सरकार और जायका के अतिरिक्त किसान परिवार की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे।

शुभ कामनाओं सहित

डॉ. सुनील चौहान
परियोजना निदेशक
एवं प्रधान सम्पादक

परियोजना निदेशक ने 82.91 लाख रुपए की सिंचाई योजना किसानों को सौंपी

कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में चल रहे फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के तहत खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई, कुल्लू की ओर से तहसील भुंतर के गांव थारस में सिंचाई योजना थारस का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरांत दिनांक 11 अप्रैल, 2025 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने की कार्यक्रम में विशेष रूप से वरिष्ठ सलाहकार बलजीत सिंह संधु और जिला परियोजना प्रबंधक, मंडी डॉ. हेम राज वर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने कृषक विकास संगठन थारस को इस सिंचाई परियोजना को औपचारिक रूप से समर्पित किया। जायका के तहत बनी इस सिंचाई योजना के निर्माण कार्य पर 82,91,588/- रुपये लागत आई इससे 35.57 हेक्टेर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, जिससे 159 किसान परिवार लाभान्वित होंगे । परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने कहा कि जायका की इन परियोजनाओं के निर्माण करवाने का मुख्य उद्देश्य फसल विविधीकरण करके किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। जायका के तहत ऐसे क्षेत्रों में पहले सिंचाई लाने के लिए कूहल का निर्माण किया जाना और इसके उपरांत किसानों को नगदी फसलों को उगाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे किसानों की आर्थिक में सुधार हो सके। इस मौके पर ग्राम पंचायत रोट-2 से ग्राम पंचायत प्रधान राजेन्द्र पाल शर्मा, कृषक विकास संगठन थारस से प्रधान प्रताप चंद, सचिव कल्पना देवी व अन्य किसानों के साथ-साथ खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई कुल्लू से खण्ड परियोजना प्रबंधक डॉक्टर गोपाल चंद भारद्वाज, निर्माण अभियंता भरत भूषण, कृषि अधिकारी सौरभ शर्मा, संजय कुमार, कनिष्ठ अभियंत्र शिवांकित धीमान, कृषि प्रसार अधिकारी कुमारी मोनिका सैनी व पर्यवेक्षक साहिल भारद्वाज उपस्थित रहे ।

मक्की की फसल में फॉल आर्मी वर्म का नियन्त्रण

फॉल आर्मीवर्म (स्पोडोप्टरा फ्रुगिपरदा) की पहचान एवं लक्षण:- मक्का पर एक नया अक्रामक कीट फॉल आर्मीवर्म का लावा पत्ती भंवर के अंदर रखकर बड़ते हुए मक्का की पत्तियां पर फोड़ करता है। क्षति के लखणों में पत्तियों का छिलना, पिन छेद, छोटे से मध्यम लम्बे छेद, समानांतर छोटे छेद और पत्तियों पर अनियमित आकार के छेद, पत्तियों के शीर्ष भाग का नुकसान, लार्वे के चबाने वाली सामग्री की उपस्थिति और पत्ती भंवर में चबाने वाली सामग्री, मल पदार्थ, खाए हुए पत्तों के ऊपर के पत्तों का गिरना

फॉल आर्मीवर्म का नियंत्रण

1. निम्नलिखित कीटनाशकों को दर्शाई गई सिफारिशों के अनुसार प्रयोग करें।

2. कीटों की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित कीटनाशकों को उपयोग का उपयोग करें। एक ही क्रिया वाले कीटनाशकों का बार-बार उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

3. स्प्रे नोजल को पत्ती भंवर की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, जिसमें लार्वा आमतौर पर फीड करते हैं।

क्र. सं.	कीटनाशक	मैन्युअल या बैटरी संचालित स्प्रेयर (500 लीटर से स्प्रे द्रव/हेक्टेयर)	पावर स्प्रेयर (150 लीटर स्प्रे द्रव/हेक्टेयर)
1.	Azadirachtin 1 ई.सी. (10000 पीपीएम)	20 मिली/10 लीटर	60 मिली/10 लीटर
2.	थायोडिकार्ब 75 डब्ल्यूपी (प्राप्त अवरोधक)	20 ग्रा./10 लीटर	60 ग्रा. / 10 लीटर
3.	Flubendiamide 480 SC (रयानोडाइन रिसेप्टर न्यूनाधिक)	3 मिली/10 लीटर	9 मिली/10 लीटर
4.	क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 एससी (रयानोडाइन रिसेप्टर न्यूनाधिक)	3 मिली/10 लीटर	9 मिली/10 लीटर
5.	क्लोरपायरोफॉस 20 ई.सी. (AchF अवरोधक)	20 मिली/10 लीटर	60 मिली/10 लीटर
6.	इमामेक्टिन बेंजोएट 5 एस.जी. (क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर)	4 ग्रा./10 लीटर	12 ग्रा./10 लीटर
7.	स्पिनोसैड 45 एससी (एनएचआर ऑलस्टेरिक न्यूनाधिक)	3 मिली/10 लीटर	9 मिली/ 10 लीटर

कीटनाशक के उपयोग के लिए सावधानियां:- यदि संभव हो तो रासायनिक स्प्रे से बचें या पूरी फसल अवधि में एक से अधिक रासायनिक स्प्रे का उपयोग नहीं करना चाहिए। कीटनाशकों की तैयारी और स्प्रे के दौरान सुरक्षात्मक कपड़े, फेसमास्क और दस्ताने का उपयोग करें। कीटनाशकों के छिड़काव के 48 घंटे बाद ही खेत में प्रवेश करें।

मक्का में फॉल आर्मीवर्म रोकथाम हेतु एकीकृत कीट प्रबंधन

पूर्व बुवाई अभ्यास

गहरे प्रकाश और शिकारी पक्षियों के लिए प्यूपा की उजागर करने के लिए खेतों में गहरी जुताई करें।

प्यूपा से वयस्क उद्भव को कम करने के लिए नीम केक 250 किग्रा/हेक्टेयर का प्रयोग करें।

प्राकृतिक शत्रुओं को आकर्षित करने के लिए खेत की मेड़ों को साफ रखें और फूलों के पौधों जैसे कि गेंदा, तिल, घोंसला, सूरजमुखी, धनिया, सौंफ आदि लगाएं।

बुवाई से छह पत्ती व सात पत्ती चरण से फूल अवस्था पर

फ्लैट बेड बुवाई के बजाय और रिज और फरो बुवाई विधि का पालन करें।

बेसल खुराक के रूप में एनपीके की केवल अनुशंसित खुराक लागू करें।

बीजोपचार साइंट्रानिलिप्रोल 19.8 प्रतिशत थायमेथेक्सम 19.8 प्रतिशत एफएस@6 मिली/ किलोग्राम बीज फसल के विकास के 15-20 दिनों तक सुरक्षा प्रदान करता है।

मक्का खेत में और आसपास वयस्क गतिविधि की निगरानी के लिए रात के घंटों के दौरान प्रकाश ट्रैप@एक/हेक्टेयर का उपयोग करें।

फॉल आर्मीवर्म के अंडों व लार्वा का हाथों से विनाश करें।

मक्का के खेतों के चारों और नैपियर घास/ संकर नैपियर की 3-4 पंक्तियां ट्रेप फसल के रूप में लगाएं।

सह कसल जैसे चना, माश, कॉऊपी आदि को 2:1 से 4:1 के अनुपात में लगाएं।

बुवाई के बाद जल्द ही फेरोमोन्स ट्रैप @/एकड़ स्थापित करें।

कीड़ों के अंडे के द्रव्यमान और लार्वा को कुचलकर विनाश करें।

पहला स्पे 5 प्रतिशत नीम के बीज की गिरी के अर्क (एनएसकेई) या अजादीरैक्टिन, 1500 पीपीएम (एक लीटर/एकड़) @ 5एमएल/लीटर पानी के साथ करें।

अंडे के परजीवी जैसे टेलोनोमस रेमुस @ 4000/एकड़ या ट्राइकोग्रामा प्रीतिओसम @ 50000/ एकड़ साप्ताहिक अंतराल पर पैरासिटोइड को खेतों में रिलीज करें।

मक्का की फसल के बाद मक्का उगाने से बचें।

यदि संक्रमण 10 प्रतिशत से अधिक है, तो फॉल आर्मीवर्म की रोकथाम हेतु नीचे दिए गए अनुशांसित कीटनाशकों में से किसी एक का इस्तेमाल करें। क्लोरेंट्रानिलिप्रोएल 18.5 एससी (80 मिली / एकड़) @ 0.4 मिली/लीटर थियामेथोक्सिम 12.6 प्रतिशत - लैम्ब्डा साइहलोथ्रिन 9-5 प्रतिशत जेडसी (50 मिली/एकड़) @ 0.25 मिली/लीटर: स्पिनेटोरम 11.7 प्रतिशत एससी (100 मिली/एकड़)@ 0.5 मिली/लीटर: इमामेक्टिन बेंजोएट 5 प्रतिशत एसजी (80 ग्राम/एकड़) 0.4 ग्राम/लीटर की सिफारिश की जाती है।

रासायनिक कीटनाशक उपयोग के लिए रासायनिक कीटनाशक के आवेदन के बीच अंतराल सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और चारे की फसल न्यूनतम 30 दिन होनी चाहिए।

फेरोमोन ट्रैप - फॉल आर्मीवर्म ल्यूर के साथ फनल ट्रैप को हर हफ्ते फसल के साथ मेल खाते हुए फसल से एक फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए। ट्रैप को न्यूनतम 75 फीट की दूरी से अलग किया जाना चाहिए। सप्ताह में दो या एक बार पकड़े गए पतंगों की संख्या के लिए ट्रैप का निरीक्षण करें।

एक एकड़ के लिए नीम के बीच की गिरी का अर्क (एनएसकेई) तैयार करना - एक एकड़ के लिए 10 किलो बीज गिरी की आवश्यकता होती है। पाउडर बनाने के लिए 10 किलोग्राम जरुरत की गुठली पीस लें। पाउडर को 50 लीटर पानी में रात भर भिगो दें। सूती कपड़े का उपयोग करके सामग्री को हिलाओ और छानो। फिल्टर्ड घोल में 200 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर या 200 मिलीलीटर साबुन का घोल डालें। पानी मिलाकर 200 लीटर तक मात्रा बनाएं।

अंडे के परजीवी के रिलीज पर सावधानी - परजीवी रिलीज और नीम रासायनिक कीटनाशकों के आवेदन के बीच न्यूनतम एक सप्ताह का अंतराल होना चाहिए।

फॉल आर्मी वर्म "जीवन चक्र"

मक्का के पौधे के शुरुआती अवस्था में तने (बाएं) या पत्ती (दाएं) पर फॉल आर्मी वर्म लार्वा के अंडे

अंडे (दाएं) व अंडों से तीन दिन बाद लार्वा निकलते हुए

अंडों से काले सिर वाले लार्वे निकलते हुए

लार्वे की बढ़ने की अवस्थाएं (1 एमएम से 45 एमएम)

मध्यम व बड़े आकार के लार्वा पर विशिष्ट चिन्ह

लाल-भूरा प्यूपा

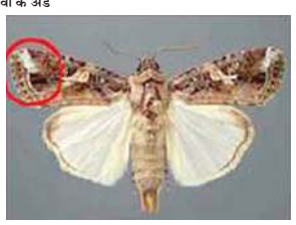

नर कीट पतंगों के अगले पंखों पर विशिष्ट सफेद निशान

फॉल आर्मी वर्म नुकसान के लक्षण

फॉल आर्मीवर्म का विनाशकारी लार्वा

'स्वस्थ भोजन है उगाना, अपने कल को है उज्जवल बनाना'

जायका समीक्षा मिशन ने मंडी जिले में कसारला उप-योजना का दौरा किया

सिंचाई योजना कृषक विकास संघ को सौंपी गई

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जायका) के दो सदस्यीय समीक्षा मिशन ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना चरण-2 के अंतर्गत निर्मित 1.08 करोड़ रुपये की लिफ्ट सिंचाई उप-परियोजना कसारला का दौरा किया। समीक्षा मिशन में परियोजना निर्माण सलाहकार सुश्री इनागाकी युकारी और विकास विशेषज्ञ सुश्री निष्ठा वेंगुर्लेकर शामिल हैं। परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान सहित अन्य लोग मिशन टीम के साथ थे।

प्रदेश में जायका कृषि परियोजना के 1010 करोड़ रुपये के दूसरे चरण की जुलाई 2021 में शुरुआत के बाद से अंतरराष्ट्रीय मिशनों का परियोजना क्षेत्र में यह छठा दौरा है। परियोजना की अवधि 2029 तक है, जिसके अंतर्गत 306 उप-परियोजनाओं के तहत 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी तथा 25,000 किसान परिवारों की समृद्धि के लिए फसल विविधीकरण के अनुकरणीय मॉडल स्थापित किए जाएंगे। समीक्षा मिशन के सदस्यों ने परियोजना के वरिष्ठ सलाहकार बलजीत सिंह संधू, वित्त अधिकारी प्रदीप शर्मा की उपस्थिति में उप-परियोजना की सिंचाई योजना का बुनियादी ढांचा भी कृषक विकास संघ को सौंपा। स्थानीय स्तर पर किसान मेला भी आयोजित किया गया, जिसमें 150 किसानों ने भाग लिया तथा समीक्षा मिशन दल ने किसानों के साझा हित समूहों तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा लाई गई आधुनिक कृषि मशीनरी तथा कृषि उपज एवं उत्पादों की प्रदर्शनी का दौरा किया।

भ्रमण के दौरान, मिशन दल ने उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से उगाई गई स्ट्रॉबेरी फसल, खीरा, टमाटर तथा अन्य प्रदर्शन भूखंडों का निरीक्षण किया। कसारला उप-परियोजना क्षेत्र मंडी जिले के बल्ह में आता है।

उप-परियोजना क्षेत्र में 75 किसान परिवार लाभान्वित होंगे, जिससे 37.38 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। इस उप-परियोजना क्षेत्र में टमाटर और फूलगोभी प्रमुख फसलें हैं।

इस अवसर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई से उप परियोजना निदेशक डॉ. राजेश कुमार (एमपीएच), डॉ. डीडी शर्मा (एई) और डॉ. करतार सिंह (एसडब्ल्यूसी) और जिला इकाई से डॉ. हेम राज, जिला परियोजना प्रबंधक मंडी और विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. खूब राम सिंह और खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. राजेश कुमार जसवाल और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

जोबरंग और यारती क्षेत्रों का जायका मिशन ने किया दौरा

महिलाओं द्वारा संचालित जनजातीय जिले में महिला समीक्षा दल

मंगलवार 29 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना द्वितीय के अंतर्गत जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में विकसित दो उप-परियोजनाओं जोबरंग और यारती-तिन्नो का दौरा किया। इस जायका समीक्षा मिशन में दोनों ही महिलाएं हैं जिन्होंने सर्व महिला प्रशासित जिला का दौरा किया। समीक्षा मिशन में परियोजना निर्माण सलाहकार सुश्री इनागाकी युकारी विकास विशेषज्ञ सुश्री निष्ठा वेंगुर्लेकर शामिल हैं।

परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान, इस जायका समीक्षा मिशन के परियोजना क्षेत्रों के चार दिवसीय दौरे में साथ हैं, जिसका समापन आगामी एक मई को होगा।

जोबरंग में किसान मेले में 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया, जबकि तिन्नो में 120 किसानों ने भाग लिया। मिशन टीम ने जोबरंग उप परियोजना क्षेत्र में ट्रांजैक्ट वॉक के दौरान आलू, फूलगोभी के खेतों और प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन भूखंडों का दौरा किया।

किसान मेलों में समीक्षा मिशन टीम ने आधुनिक कृषि मशीनरी की प्रदर्शनी का दौरा किया और किसानों के साझा हित समूहों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लाए गए कृषि उपज और उत्पादों को देखा।

समीक्षा यात्राओं के दौरान परियोजना के वरिष्ठ सलाहकार बलजीत सिंह संधू, वित्त अधिकारी प्रदीप शर्मा भी मौजूद थे। उप-परियोजना जोबरंग लाहौल - स्पीति जिले के अंतर्गत आती है और इसका निर्माण 72.29 लाख रुपये की लागत से किया गया है। यह 55.66 हेक्टेयर कमांद क्षेत्र को कवर करती है और 84 परिवारों को लाभान्वित करेगी ।

आलू, मटर और फूलगोभी इस उप-परियोजना की प्रमुख व्यापरिक फसलें हैं। दूसरी ओर, उप-परियोजना यारती-तिन्नो लाहौल और स्पीति जिले की कोलोंग पंचायत के अंतर्गत आती है।

उप-परियोजना का प्रवाह सिंचाई बुनियादी ढांचा 55.10 लाख रुपये की लागत से बनाया गया है, जो 35 किसान परिवारों को लाभान्वित करते हुए 25 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को कवर करता है। आलू और मटर इस उप-परियोजना की प्रमुख व्यापरिक फसलें हैं।

इस अवसर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई से उप परियोजना निदेशक डॉ. राजेश कुमार (एमपीएच), डॉ. डीडी शर्मा (एई) और डॉ. करतार सिंह (एसडब्ल्यूसी), पीएमसी के सह-टीम लीडर इंजी. अनिल अग्रवाल और कृषि विशेषज्ञ डॉ. आरके शर्मा, जिला परियोजना प्रबंधक मंडी डॉ. हेम राज और ब्लॉक परियोजना प्रबंधक-कुल्लू डॉ. गोपाल चंद भारद्वाज और जिला इकाई के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

कटली नाला में जायका मिशन ने पहुंच मार्ग किसानों को सौंपा

हिमाचल प्रदेश जायका कृषि परियोजना के दौरे के तीसरे दिन बुधवार को दो सदस्यीय जायका समीक्षा मिशन ने मंडी जिले में कटली नाला उप परियोजना के कृषक विकास संघ (केवीए) को 1.4 किलोमीटर लंबे कृषि पहुंच मार्ग का लोकार्पण किया। समीक्षा मिशन में परियोजना निर्माण सलाहकार सुश्री इनागाकी युकारी विकास विशेषज्ञ सुश्री निष्ठा वेंगुर्लेकर शामिल हैं, जबकि परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान परियोजना क्षेत्र के दौरे के दौरान मिशन टीम के साथ रहे।

जायका समीक्षा मिशन ने लाभार्थी किसानों द्वारा आयोजित स्थानीय किसान मेले में भाग लिया तथा आधुनिक कृषि मशीनरी, कृषि उपज तथा किसानों व स्वयं सहायता समूहों के साझा हित समूहों द्वारा लाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया।

कटली नाला से ननवाहन पपलेहरा उप-परियोजना जिला मंडी की पंचायत मराठू में स्थित है। इस सिंचाई उप-परियोजना का निर्माण 1,29,91,226 रुपये की लागत से किया गया है, जिससे 23.90 हेक्टेयर कमांद क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिली है तथा इसके निर्माण से 38 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रमुख फसलों में खरीफ सीजन में टमाटर, अदरक तथा रबी सीजन में लहसुन, प्याज तथा फूलगोभी शामिल हैं। किसानों के लिए मंडी स्थित कृषि विपणन केंद्र सबसे नजदीक है। इस अवसर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई से उप परियोजना निदेशक डॉ. राजेश कुमार (एमपीएच), डॉ. डीडी शर्मा (एई) और डॉ. करतार सिंह (एसडब्ल्यूसी), पीएमसी से सह-टीम लीडर इंजीनियर अनिल अग्रवाल और डॉ. आरके शर्मा, जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. हेम राज और विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. खूब राम सिंह और खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. राजेश कुमार जसवाल और जिला इकाई के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 (जायका ओडीए) के स्वामित्व में परियोजना निदेशक द्वारा परियोजना भवन, कृषि परिसर, हमीरपुर-177001 से संपादित, प्रकाशित एवं मुद्रित।
फोन: 01972-223059. ई-मेल : iechpjicaagriculture9@gmail.com, Website: www.hpjicaagriculture.com